Samyak
An Institute For Civil Services

Model Answer

Que. The recent surge in gold loan NPAs underscores ongoing challenges in managing non-performing assets in India. What are Non-Performing Assets (NPAs), and why do they pose a significant challenge to the Indian banking sector? Discuss the steps taken by the government and the Reserve Bank of India (RBI) to tackle this issue.

Non-Performing Assets (NPAs) are loans or advances where the principal or interest payment has been overdue for 90 days or more. They reflect the inability of borrowers to repay, leading to financial strain on the banking sector. The recent surge in gold loan NPAs highlights the pressing need to address this persistent challenge in India.

Significant Challenge

1. **Erosion of Bank Profits:** NPAs reduce the income banks earn from interest, directly affecting their profitability.
2. **Capital Constraints:** Increased NPAs force banks to set aside higher provisions, limiting their ability to lend further.
3. **Investor Confidence:** High NPAs lead to a loss of trust among investors and depositors, affecting the stability of banks.
4. **Economic Impact:** A high level of NPAs can restrict credit flow to productive sectors, hampering economic growth.
5. **Rising Operational Costs:** Recovering bad loans involves legal and administrative expenses, further burdening banks.

Steps Taken by the Government and RBI

1. **Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016:** Provides a structured framework for resolving insolvencies efficiently and transparently.
2. National Asset Reconstruction Company Limited **(NARCL**) & India Debt Resolution Company Ltd. **(IDRCL)** has been established.
3. **SARFAESI Act, 2002:** Enables banks to auction properties of defaulters to recover dues.
4. **Asset Reconstruction Companies (ARCs):** Facilitate the purchase of stressed assets to clean up bank balance sheets. There are 28 ARC's working in India right now.
5. **RBI's Prompt Corrective Action (PCA) Framework:** Places restrictions on banks with high NPAs, ensuring corrective measures.
6. **Public Sector Bank Recapitalization:** Infusion of capital into public sector banks to strengthen their financial position.
7. **One-Time Loan Restructuring Schemes:** Offers relief to stressed borrowers while minimizing the chances of loans turning into NPAs.
8. **Digital Monitoring Systems:** Use of AI and data analytics to identify early signs of stress in loans.
9. The 4R Strategy to deal with NPAs involves **Recognition** through timely identification of stressed assets, **Resolution** via mechanisms like IBC and recovery tribunals, **Recapitalization** to strengthen banks' balance sheets, and **Reforms** to enhance credit assessment frameworks and prevent future NPAs.

NPAs remain a significant challenge to India's banking sector, demanding a multipronged approach combining regulatory measures, legal reforms, and technological interventions. While initiatives like the IBC and PCA framework have shown promise, a robust and proactive credit monitoring system is essential to sustain long-term financial stability and economic growth.

Model Answer

प्रश्न: हाल में गोल्ड लोन एनपीए (Non-Performing Assets) में वृद्धि ने भारत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के प्रबंधन में मौजूद चुनौतियों को उजागर किया है। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) क्या हैं, और वे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती क्यों बनती हैं? इस समस्या से निपटने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs): *गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) वे ऋण या अग्रिम होते हैं जिनमें मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों या उससे अधिक समय तक बकाया रहता है। ये उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान करने की अक्षमता को दर्शाती हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र पर वित्तीय दबाव डालती हैं। हाल में गोल्ड लोन एनपीए में वृद्धि ने इस चुनौती की गंभीरता को और उजागर किया है।*

<u>बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौती:</u>

1. ***बैंक के मुनाफे में कमी:*** *एनपीए बैंकों की ब्याज से होने वाली आय को कम कर देते हैं, जिससे उनकी लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।*
2. ***पूंजी सीमाएं:*** *एनपीए में वृद्धि के कारण बैंकों को अधिक प्रावधान करना पड़ता है, जिससे वे नए ऋण देने में सक्षम नहीं हो पाते।*
3. ***निवेशक विश्वास:*** *उच्च एनपीए निवेशकों और जमाकर्ताओं का विश्वास कम करते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता प्रभावित होती है।*
4. ***आर्थिक प्रभाव:*** *एनपीए का उच्च स्तर उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सीमित कर देता है, जिससे आर्थिक विकास बाधित होता है।*
5. ***ऑपरेशनल लागत में वृद्धि:*** *खराब ऋणों की वसूली में कानूनी और प्रशासनिक खर्च शामिल होते हैं, जो बैंकों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं।*

<u>सरकार और RBI द्वारा उठाए गए कदम:</u>

1. ***दीवालिया और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016:*** *यह दिवालियापन को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से हल करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है।*
2. ***एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) & भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL)*** *की स्थापना।*
3. ***SARFAESI अधिनियम, 2002:*** *बैंकों को बकायादारों की संपत्ति की नीलामी के माध्यम से बकाया वसूलने में सक्षम बनाता है।*
4. ***एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां (ARCs):*** *बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की खरीद को सक्षम बनाती हैं; अभी भारत में 28 एआरसी काम कर रही हैं*
5. ***RBI की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) रूपरेखा:*** *उच्च एनपीए वाले बैंकों पर प्रतिबंध लगाकर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करती है।*

6. ***सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण:*** *सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी प्रवाह बढ़ाकर उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना।*
7. ***एक बार ऋण पुनर्गठन योजना:*** *तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करती है और ऋणों को एनपीए बनने से रोकती है।*
8. ***डिजिटल निगरानी प्रणाली:*** *ऋणों में तनाव के शुरुआती संकेतों की पहचान के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग।*
9. ***4R रणनीति:***
    - *पहचान (Recognition): तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की समय पर पहचान।*
    - *संकल्प (Resolution): IBC और वसूली ट्रिब्यूनल जैसे तंत्रों के माध्यम से समाधान।*
    - *पुनर्पूंजीकरण (Recapitalization): बैंकों की बैलेंस शीट को मजबूत करना।*
    - *सुधार (Reforms): ऋण आकलन ढांचे को बेहतर बनाना और भविष्य के एनपीए को रोकना।*

एनपीए भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक प्रमुख चुनौती बने हुए हैं, जिन्हें दूर करने के लिए नियामक उपायों, कानूनी सुधारों और तकनीकी हस्तक्षेपों के समन्वय की आवश्यकता है। IBC और PCA जैसी पहलों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत और सक्रिय ऋण निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है।

Samyak
An Institute For Civil Services